The Lengthiest Written Constitution in the World

विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान

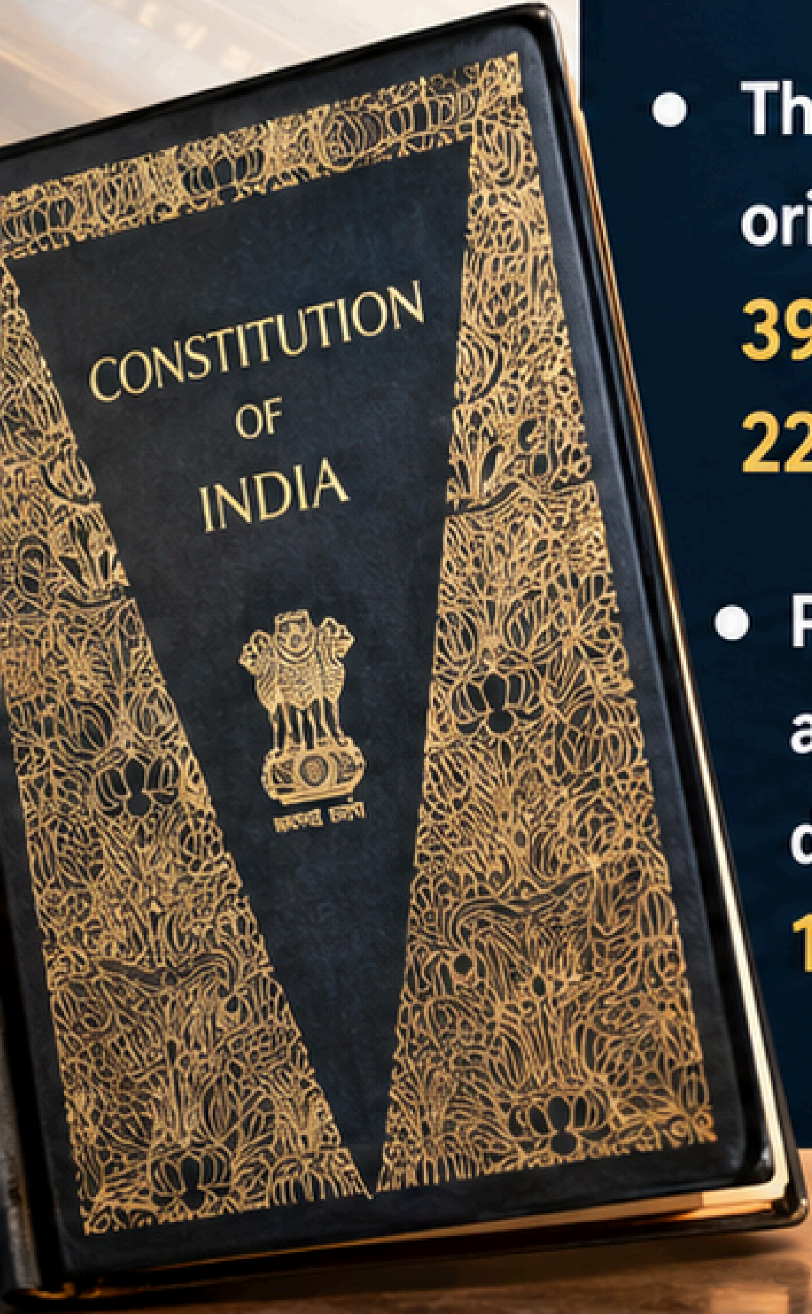

- The Indian Constitution originally consisted of **395 articles** divided into **22 Parts** and **8 Schedules**.
- Presently, it consists of a Preamble, **448 articles** divided into **25 Parts** and **12 Schedules**.

- भारतीय संविधान मूल रुप से **395 अनुच्छेदों** का था, जिसे **22 भागों** और **8 अनुसूचियों** में विभाजित किया गया था।
- वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना (Preamble) और **448 अनुच्छेद** हैं, जिन्हें **25 भागों** और **12 अनुसूचियों** में विभाजित किया गया है।

JRF Media Academy by Rohit

Rohit Yadav

PhD Scholar at
Central University of Rajasthan

JRF Media Academy

UGC-NET

PAPER 1

FULL COURSE

Let's Find Out Every Concept in Detail.

- COMPLETE SYLLABUS – TOPIC WISE
- LATEST PYQ's WITH DETAILED SOLUTIONS
- TOPIC-WISE VIDEO LECTURES
- HINDI & ENGLISH

+ MASS COMMUNICATION
PAPER 2
FULL COURSE

UGC-NET *by Rohit*

UGC-NET Paper 1 Complete Syllabus with Latest PYQ's Solutions.

PREAMBLE

प्रस्तावना

- America was the 1st to begin with a Preamble
- अमेरिका वह पहला देश था जिसने प्रस्तावना की शुरुआत की।

- Preamble refers to intro/ preface of the constitution
- प्रस्तावना संविधान की भूमिका या प्रारंभिक परिचय को संदर्भित करती है।

- N.A. Palkhivala called it 'identity card of the constitution'
- एन. ए. पालखिवाला ने इसे संविधान का 'पहचान पत्र' कहा।

- Based on objective resolution, drafted and moved by Pandit Nehru on 13 december 1946 and adopted by Constituent assembly on 22 january 1947
- उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया।

- A preamble is an introductory statement in a constitution, statute, or legal document that explains its underlying philosophy, purpose, and objectives.
- प्रस्तावना संविधान, विधि या किसी कानूनी दस्तावेज में एक प्रारंभिक कथन होता है, जो उसके मूल दर्शन, उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट करता है।

- The words, "Socialist" and "Secular" were adden in the Preamble of the constitution by 42nd ammendment which was passed in 1976.
- "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द्र संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, जो 1976 में पारित हुआ था।

- The constitution declares India to be a Sovereign, Socialist, Democratic, Republic.
- संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य घोषित करता हैं।

JRF Media Academy by Rohit

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE | प्रस्तावना

THE CONSTITUTION OF INDIA
PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, *having solemnly resolved to constitute India into a* ***¹[SOVEREIGN, SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]*** *and to secure to all its citizens:*

JUSTICE, *social, economic and political;*

LIBERTY *of thought, expression, belief, faith and worship;*

EQUALITY *of status and of opportunity; and to promote among them all*

FRATERNITY *assuring the dignity of the individual and the ²[unity and integrity of the Nation];*

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY *this twenty –sixth day of November, 1949 do* ***HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.***

1. *Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)*
2. *Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)*

English	हिन्दी
WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **'SOVEREIGN, SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens:	हम, भारत के लोग, भारत को एक 'संपुर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को:
JUSTICE, social, economic and political;	न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;	स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की;
EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all	समानता, स्थिति और अवसर की; तथा उन सब में
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the ²[unity and integrity of the Nation];	व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता को बढ़ावा देने के लिए
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty –sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**	हमारी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत दो हजार छः विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

JRF Media Academy by Rohit

COMPONENTS OF PREAMBLE

प्रस्तावना के घटक

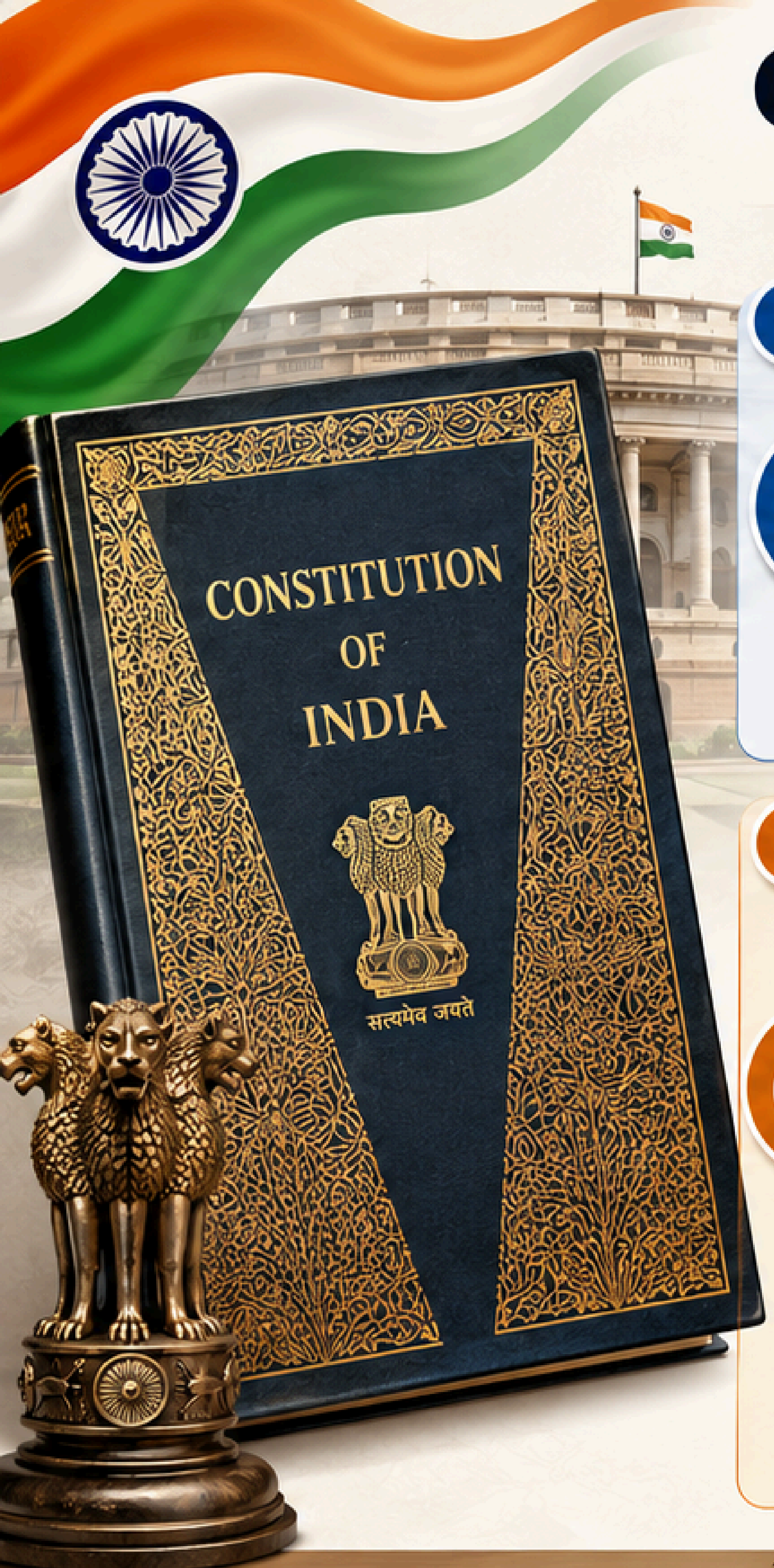

1

Source of Authority: The Preamble explicitly states that the Constitution derives its authority from the people of India ("We, the people...").

अधिकार का स्रोत: प्रस्तावना स्पष्ट रूप से कहती है कि संविधान को अपनी शक्ति भारत के लोगों से मिलती है ("हम, भारत के लोग...").

2

Nature of the Indian State: It declares India to be a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, and Republic polity.

भारतीय राज्य का स्वरूप: यह भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करता है।

Nature of the Indian State — भारतीय राज्य का स्वरूप

- Sovereign सार्वभौम
- Socialist समाजवादी
- Secular धर्मनिरपेक्ष
- Democratic लोकतांत्रिक
- Republic गणराज्य

3

Objectives of the Constitution: It specifies the core goals of the nation: Justice (social, economic, political), Liberty (of thought, expression, belief, faith, and worship), Equality (of status and opportunity), and Fraternity (ensuring the dignity of the individual and the unity/integrity of the nation)

संविधान के उद्देश्य: यह राष्ट्र के मूल लक्ष्यों को निर्धारित करता है: न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की), समानता (स्थिति और अवसर की), और बंधुत्व (व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता/अखंडता को सुनिश्चित करना)

4

Date of Adoption: It states that the Constituent Assembly adopted the Constitution on November 26, 1949.

स्वीकरण की तिथि: यह बताता है कि संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अपनाया।

SOVEREIGN

सार्वभौम

India is internally and externally sovereign

Free to:

Frame its own laws
अपने स्वयं के कानून बनाने के लिए स्वतंत्र

Conduct foreign relations
विदेश संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र

India has its own independent authority, and it is not a dominion of any other external power. In the country, the legislature has the power to make laws which are subject to certain limitations.

भारत की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का अधीनस्थ नहीं है। देश में, विधायिका को कानून बनाने की शक्तित है, जो कुछ सीमाओं के अधीन है।

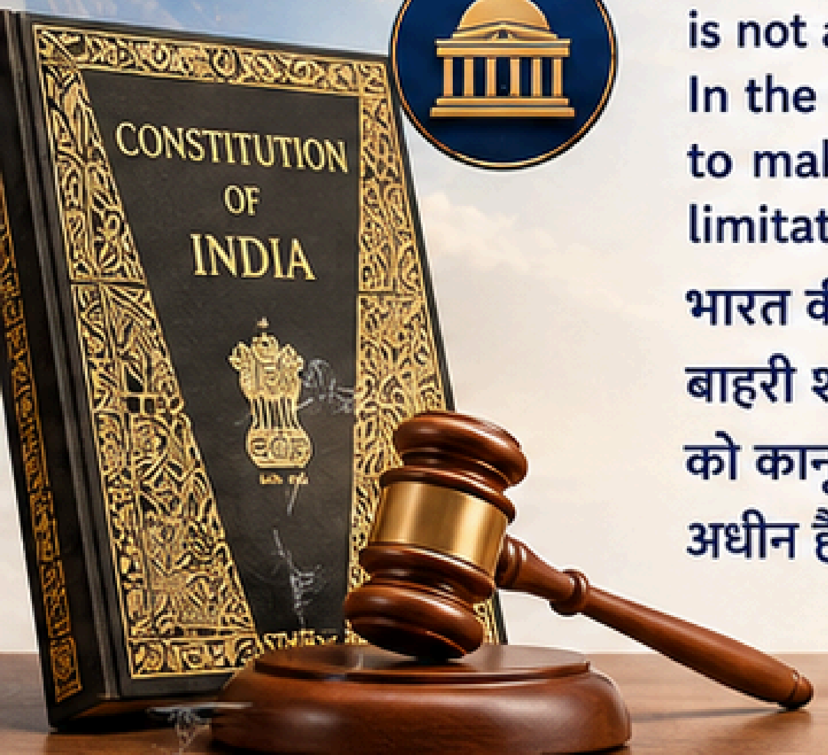

SOCIALIST

समाजवादी

The word “Socialist” appears in the Preamble after the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976

“समाजवादी” शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के बाद प्रस्तावना में जोड़ा गया।

Earlier, implicilty present in the form of DPSP

इससे पहले, यह DPSP के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद था।

India follows democratic socialism:

- mixed economy (public + private sectors)
- Focus on ending poverty, ignorance, disease, inequality of opportunity

भारत लोकतांत्रिक समाजवाद का पालन करता है:

- मिश्रित अर्थव्यवस्था (सार्वजनिक + निजी क्षेत्र)
- गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित

SECULAR
धर्मनिरपेक्ष

Added in 42nd Amendment Act of 1976.	• 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 में जोड़ा गया।
The state has no official religion and treats all faiths equally.	राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी आस्थाओं के साथ समान व्यवहार करता है।
Positive concept of secularism - all religions have equal status and support from the state	धर्मनिरपेक्षता की सकाराम्मक अवधारणा - सभी धर्मों को समान दर्जा और राज्य का समर्थन प्राप्त है।
For example, Article 25-28 Right to freedom of religion.	उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
Article 25 of the Indian Constitution guarantees all persons the fundamental right to freedom of conscience and to profess, practice, and propagate religion.	भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

DEMOCRATIC
लोकतांत्रिक

• India is a Democracy (ruled by the people)	भारत एक लोकतंत्र है (जनता द्वारा शासित)
• Based on popular sovereignty (power lies with the people)	लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित (सत्ता जनता में निहित होती है)

Democracy is of two types- direct and indirect
लोकतंत्र दो प्रकार का होता है - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष

• India has an indirect (representative) democracy	भारत में अप्रत्यक्ष (प्रतिनिधि) लोकतंत्र है
• Universal adult franchise, free and fair, periodic elections	सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष, समय-समय पर चुनाव
• Based on Social and economic democracy, not just political democracy	सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर आधारित, केवल रजनीतिक लोकतंत्र नहीं

CONSTITUTION OF INDIA
सत्यमेव जयते

JRF Media Academy by Rohit

Republic
गणतंत्र

- Two main categories: Monarchy and Republic
  दो मुख्य श्रेणियाँ: राजशाही और गणतंत्र
- Monarchy: The head of state is typically hereditary.
  राजशाही: राज्य प्रमुख आमतौर पर वंशानुगत होता है।
- Republic: The head of state is always elected, either directly or indirectly, for a fixed term.
  गणतंत्र: राज्य प्रमुख हमेशा निर्वाचित होता है, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, निश्चित अवधि के लिए।
- In India, the head of state is elected for a period of five years.
  भारत में, राज्य प्रमुख का चुनाव पाँच वर्ष की अवधि के लिए होता है।
- Unlike in a monarchy, the head of state in a republic does not inherit their position.
  राजशाही के विपरीत, गणतंत्र में राज्य प्रमुख अपना पद वंशानुगत रूप से प्राप्त नहीं करता।
- A republic signifies that political sovereignty lies with the people rather than a single ruler, such as a king.
  गणतंत्र का अर्थ है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक शासक, जैसे राजा, के बजाय जनता में निहित होती है।
- There is no class privilege; all positions are accessible to everyone.
  कोई वर्ग विशेषाधिकार नहीं; सभी पद सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं।

JUSTICE
न्याय

- Idea of Justice has been taken from Russian revolution
  न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ली गई है।

- SOCIAL - equal status, no discrimination, improvement in conditions of backward classes
  सामाजिक - समान स्थिति, कोई भेदभाव नहीं, पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार

- ECONOMIC - reduce economic inequalities
  आर्थिक - आर्थिक असमानताओं को कम करना

- POLITICAL - equal political rights
  राजनीतिक - समान राजनीतिक अधिकार

LIBERTY
स्वतंत्रता

Thought, expression, belief, faith, worship	विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा
Absence of restraint on the activities of individuals and providing opportunities for the development of individual personalities	व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव और व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करना
Not a license, Reasonable restrictions	यह कोई लाइसेंस नहीं है, उचित प्रतिबंध
It is not Absolute	यह पूर्ण नहीं है
Concept of liberty, equality & fraternity taken from French Revolution	स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई

EQUALITY
समानता

Equality of status and opportunity	स्थिति और अवसर की समानता
Absence of special privileges and provision to adequate opportunities	विशेषाधिकारों का अभाव और पर्याप्त अवसर प्रदान करना
Based on 3 components - civic, political and economic	3 घटकों पर आधारित - नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक
CIVIC EQUALITY - Article 14, Article 17	नागरिक समानता - अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17
POLITICAL EQUALITY - Two provisions ◦ Article 325 no person to be declared ineligible for inclusion in electoral rolls on grounds of religion, race, caste or sex ◦ Article 326 - universal adult suffrage	राजनीतिक समानता - दो प्रावधान ◦ अनुच्छेद 325 धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर किसी को भी मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा ◦ अनुच्छेद 326 - सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
ECONOMIC EQUALITY - Article 39 DPSP	आर्थिक समानता - अनुच्छेद 39 DPSP

FRATERNITY
भ्रातृत्व

Fraternity means a sense of brotherhood and harmony

भ्रातृत्व का अर्थ है भाईचारा और सद्भाव की भावना

Article 51A (fundamental duty) - it shall be duty of every citizen of India to promote harmony and spread of common brotherhood

अनुच्छेद 51A (मूल कर्तव्य) - यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह सद्भाव को बढ़ावा दे और सामान्य भाईचारा फैलाए

Preamble declares that Fraternity Ensure two things -
- dignity of the individual
- unity and integrity of the nation

प्रस्तावना घोषित करती है कि भ्रातृत्व दो चीजें सुनिश्चित करता है -
- व्यक्ति की गरिमा
- राष्ट्र की एकता और अखंडता

Integrity added by 42nd CAA

अखंडता जोड़ी गई 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा

PREAMBLE PART OF THE CONSTITUTION?
क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है?

- **Berubari union case 1960** - that preamble is a key to the minds of the makers of the Constitution, butnot a part of the Constitution

  बेरुबारी यूनियन केस 1960 - कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के विचारों की कुंजी है, लेकिन संविधान का भाग नहीं है।

- In case of **Kesavananda Bharti case 1973**, overruled its earlier stance and Supreme Court considered preamble a part of a constitution

  केशवानंद भारती केस 1973 के मामले में, अपने पूर्व के निर्णय को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना।

- **LIC of India case 1995**, again, preamble is a part of Constitution

  एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995, फिर से, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।

- Contemporary relevance- yes, still part of Constitution, but

  समकालीन प्रासंगिकता- हां, यह अभी भी संविधान का हिस्सा है, लेकिन
  - Preamble is not a source of power to legislature

    प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है
  - It is non justiciable

    यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है

CAN PREAMBLE BE AMENDED?
क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है?

- Article 368 power of parliament to amend constitution

  अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है।

- Can be amended without altering the basic feature (kesavanand bharti case

  मूल संरचना को बदले बिना संशोधित किया जा सकता है (केशवानंद भारती केस)

- Amended ONLY once by 42nd CAA 1976

  केवल एक बार 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया

- ADDED 3 WORDS
  - SOCIALIST
  - SECULAR
  - DEMOCRATIC

  3 शब्द जोड़े गए
  - समाजवादी
  - पंथनिरपेक्ष
  - लोकतांत्रिक

JRF Media Academy by Rohit

THE PREAMBLE OF THE INDIAN CONSTITUTION – IMPORTANT MCQs

भारत के संविधान की प्रस्तावना – महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1 **The Preamble of the Constitution of India emphasises on:-**

भारत के संविधान की प्रस्तावना किन बातों पर बल देती है?-

A. Justice (न्याय)
B. Liberty (स्वतंत्रता)
C. Equality (समानता)
D. Monarchy (राजतंत्र)
E. Fraternity (बंधुत्व)

Options / विकल्प :

1. A, B, D Only / केवल A, B, D
2. A, C, D Only / केवल A, C, D
3. A, C, E Only / केवल A, C, E

✔ **4. A, B, C, E Only / केवल A, B, C, E**

2 **The words 'Secular' was added to the Preamble of the Indian Constitution by the**

संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

(a) 39th Amendment (39वाँ संशोधन)
(b) 41th Amendment (41वाँ संशोधन)
(c) 42nd Amendment (42वाँ संशोधन)
(d) 44th Amendment (44वाँ संशोधन)

✔ **(c) 42nd Amendment (42वाँ संशोधन)**

3 **The correct sequence mentioned in the Preamble is?**

प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम कौन सा है?

(a) A Sovereign, Democratic, Republic
(a) एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य
(b) A Socialist, Democratic, Republic
(b) एक समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य
(c) A Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic
(c) एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य
(d) None of these / इनमें से कोई नहीं

✔ **(c) A Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic**
(c) एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य

4 **The ideal of justice-social, economic and political has been taken from which Revolution?**

न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं?

(a) French Revolution (फ्रांसीसी क्रांति)
(b) Russian Revolution (रूसी क्रांति)
(c) American Revolution (अमेरिकी क्रांति)
(d) Glorious Revolution (ग्लोरियस क्रांति)

✔ **(b) Russian Revolution (रूसी क्रांति)**

5 **In which case did the Supreme Court declare the Preamble as part of the basic structure of the Constitution?**

सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया?

(a) Beru Bari Case (बेडू बारी केस)
(b) A.K. Gopalan Case (ए.के. गोपालन केस)
(c) Privy Purse Case (प्रिवी पर्स केस)
(d) Keshavanand Bharti Case (केशवानंद भारती केस)

✔ **(d) Keshavanand Bharti Case (केशवानंद भारती केस)**

Note: The Preamble is the soul of the Constitution. / नोट: प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।

FUNDAMENTAL RIGHTS

मौलिक अधिकार

The Indian Constitution provides for six fundamental rights that safeguard the individual's liberties and rights against the state's encroachments, ensuring equality, freedom, religion, culture, education, and constitutional remedies.

भारतीय संविधान छह मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हैं तथा राज्य के अतिक्रमणों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे समानता, स्वतंत्रता, धर्म, संस्कृति, शिक्षा और संवैधानिक उपचार सुनिश्चित होते हैं।

Article 12 to 35 contained in Part III of the Constitution deal with Fundamental Rights.

अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग III में मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं।

Part III is also referred to as Magna Carta of Indian Constitution.

भाग III को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है।

One can approach the Supreme Court directly in case of violation of Fundamental Rights.

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।

{ Fundamental Rights }

These rights are known as "fundamental" as they are the most essential for all-round development i.e., material, intellectual, moral and spiritual and protected by fundiamental law of the land i.e. constitution.

इन अधिकारों को "मौलिक" कहा जाता है क्योंकि ये सर्वांगीण विकास के लिए सबसे आवश्यक हैं, अर्थात् भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक तथा देश के मौलिक कानून, अर्थात् संविधान द्वारा संरक्षित हैं।

सत्यमेव जयते

PREAMBLE OF THE INDIAN CONSTITUTION

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

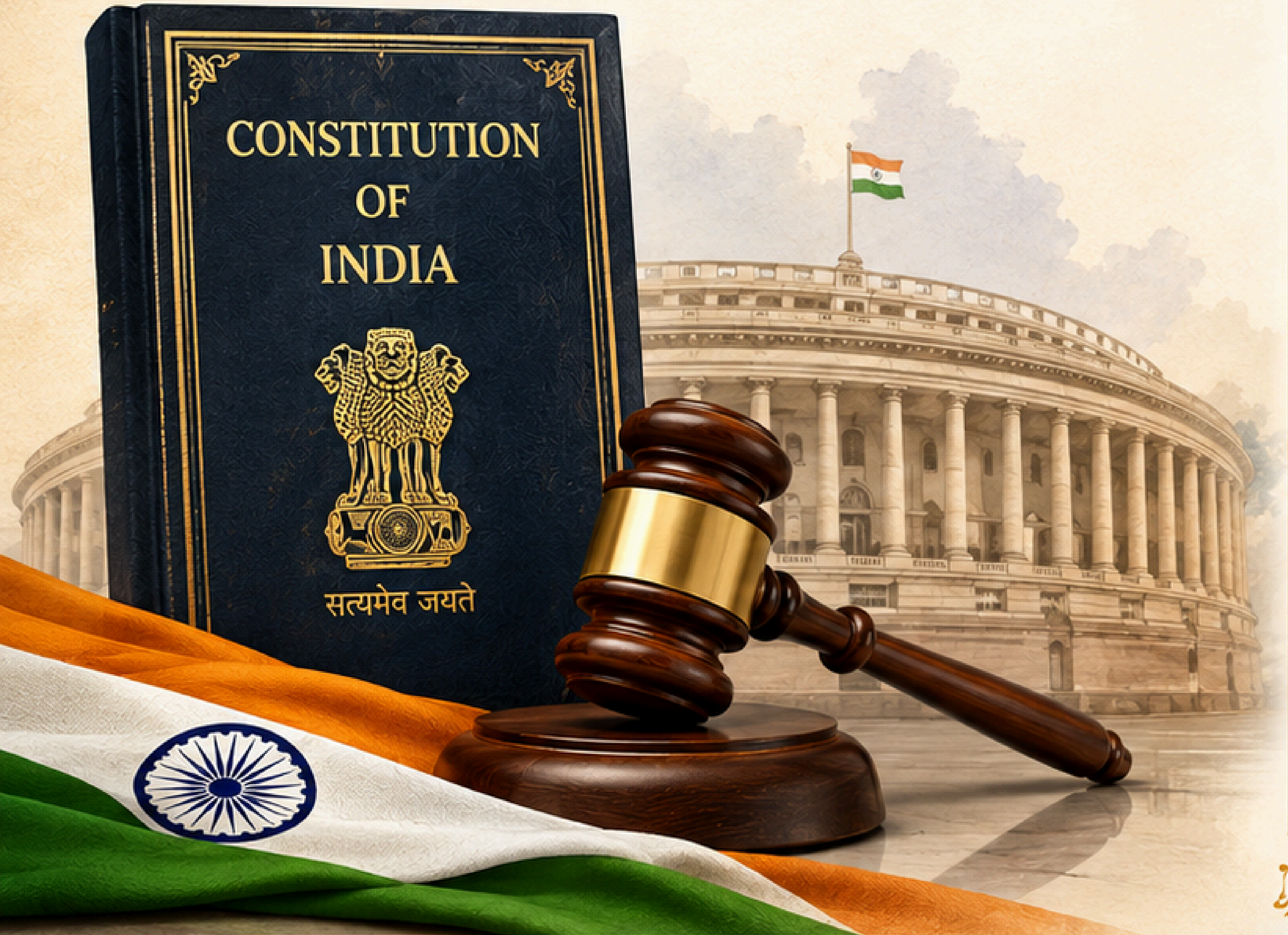

JRF Media Academy by Rohit

FUNDAMENTAL RIGHTS

मौलिक अधिकार

1. **Right to Equality** (Article 14-18)
   समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
2. **Right to Freedom** (Article 19-22)
   स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
3. **Right against Exploitation** (Article 23-24)
   शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
4. **Right to Freedom of Religion** (Article 25-28)
   धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
5. **Cultural and Educational Rights** (Article 29-30)
   सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
6. **Right to Constitutional Remedies** (Article 32-35)
   संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32-35)

Judicial Review

न्यायिक समीक्षा

Judicial review in India is a process by which the Supreme Court and the High Courts of India examine, determine and invalidate the Executive or Legislative actions inconsistent with the Constitution of India.

भारत में न्यायिक समीक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कार्यपालिका या विधायिका के उन कार्यों की जांच करते हैं, निर्धारित करते हैं और उन्हें अमान्य घोषित करते हैं जो भारत के संविधान के असंगत हैं।

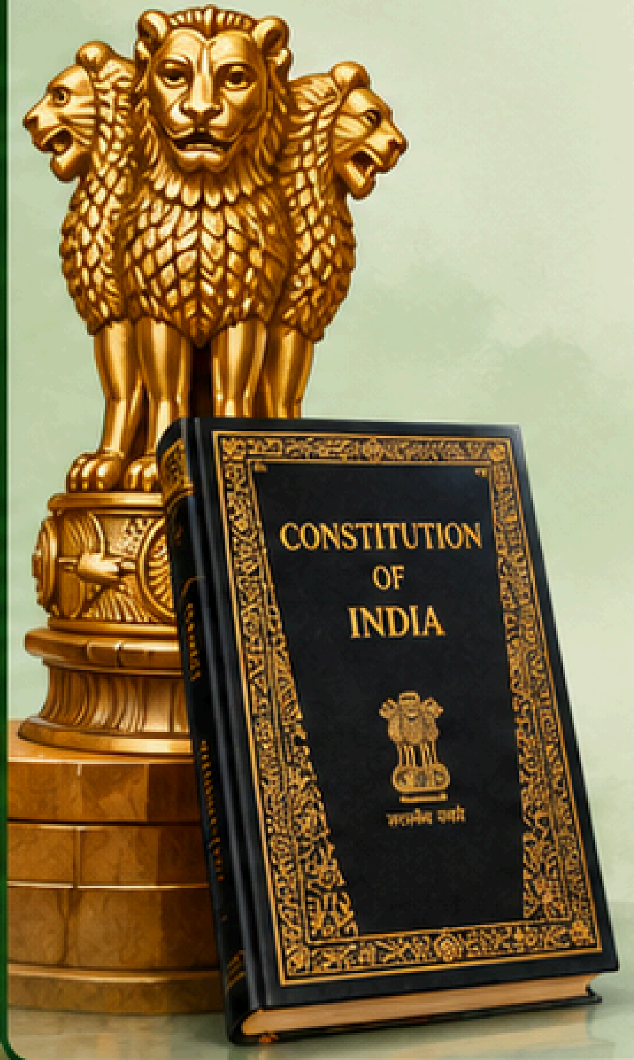

Blend of Rigidity and Flexibility

कठोरता और लचीलापन का अनूठा मिश्रण

The Indian Constitution is a unique blend of rigidity and flexibility

भारतीय संविधान कठोरता और लचीलापन का एक अनूठा मिश्रण हैं।

A rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment, for example, the American Constitution.

एक कठोर संविधान वह होता है जिसमें संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे अमेरिकी संविधान में।

A flexible constitution is one that can be amended in the same manner as ordinary laws are made.

एक लचीला संविधान वह होता है जिसमें आम कानूनों की तरह ही संशोधन किया जा सकता है।

This unique characteristic allows it to adapt to changing circumstances while also providing stability and protection for fundamental principles.

यह अनूठी विशेषता इसे बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की अनुमति देती है साथ ही मौलिक सिद्धांतों के लिए स्थिरता और सुरक्षा भी प्रदान करती है।

Article 368 deals with the power of Parliament to amend the Constitution and the procedure thereof. It keeps a check on the arbitrary power of the Parliament of India.

अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। यह भारत की संसद की मनमानी शक्ति पर नियंत्रण रखता है।

JRF Media Academy by Rohit

Parliamentary Form of Government
संसदीय शासन प्रणाली

- The Constitution of India establishes a parliamentary form of government both at the Centre and the States.
  भारत का संविधान केंद्र और राज्यों दोनों में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है।
- In a Parliamentary form of government, the Prime Minister and Council of Ministers are responsible for all their actions to the government, particularly to the Lower House, Lok Sabha.
  संसदीय शासन प्रणाली में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए सरकार के प्रति, विशेष रूप से निचले सदन, लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- When they loose their confidence with the people they should resign. When they refuse to resign the opposition parties will move a noconfidence motion and remove the government from power.
  जब वे जनता का विश्वास खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वे इस्तीफा देने से इनकार करते हैं, तो विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को सत्ता से हटा सकते हैं।

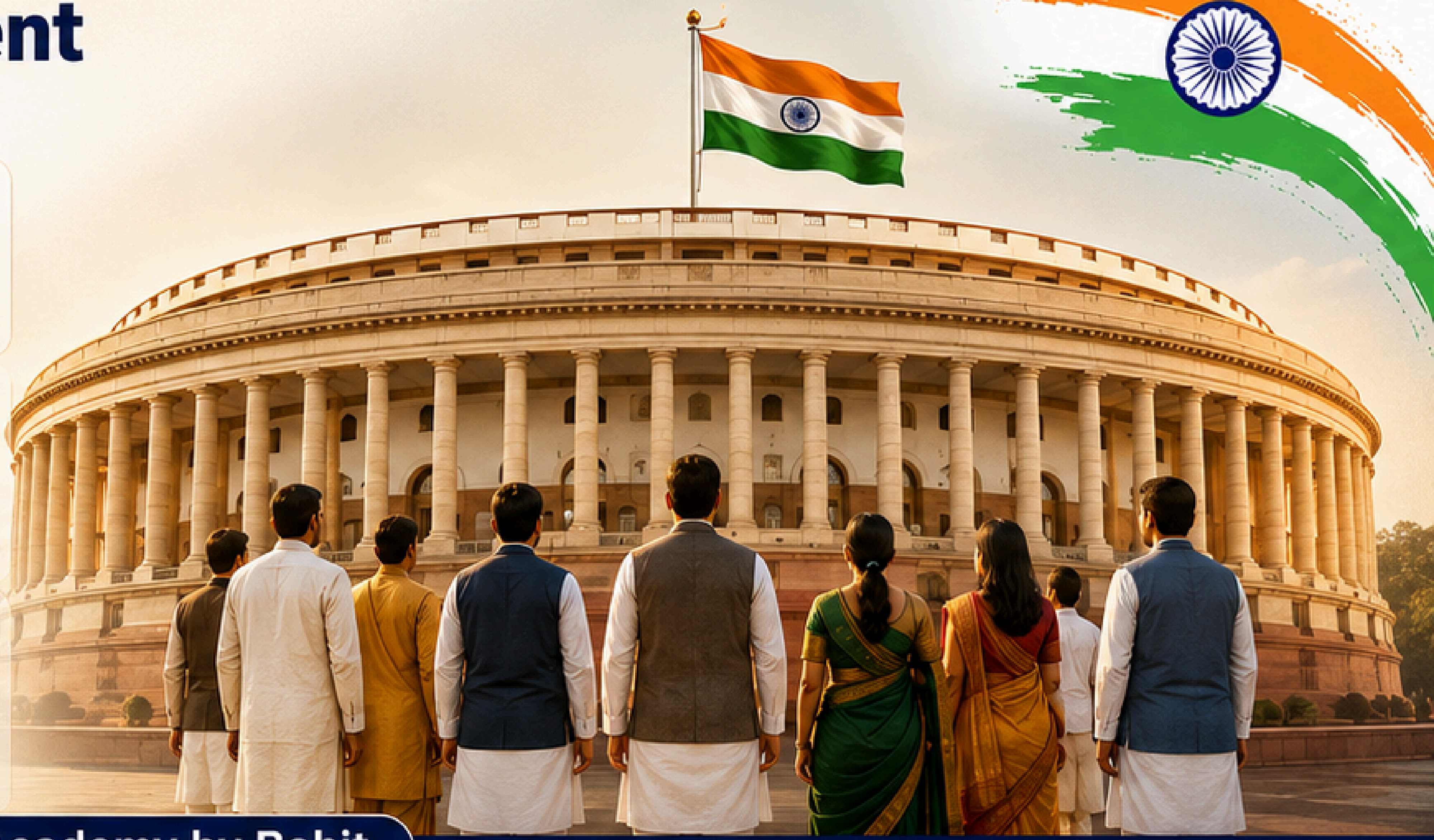

JRF Media Academy by Rohit

Single Citizenship
एकल नागरिकता

- The Constitution of India gives single citizenship to the people of the country. All the people irrespective of the states or territories in which they reside are the citizens of the country.
  भारत का संविधान देश के लोगों को एकल नागरिकता प्रदान करता है।
  राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों चाहे वे जिस में भी रहते हों, सभी लोग देश के नागरिक होते हैं।
- This is unlike USA, where a citizen is a citizen of USA and the state in which he/she resides.
  यह अमेरिका से भिन्न है, जहां कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिक और उस राज्य का नागरिक होता है जहां वह रहता है।

Parliamentary Privileges

संसदीय विशेषाधिकार

- Parliamentary privileges are special rights, immunities, and exemptions that members of Parliament and their committees enjoy.
  संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकार, प्रतिरक्षा और छूट हैं जो संसद और उनकी समितियों के सदस्यों को प्राप्त होते हैं।
- These privileges are defined in Article 105 of the Indian Constitution.
  इन विशेषाधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में परिभाषित किया गया है।
- It has been borrowed from British constitution.
  यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।
- The members of parliament are entitled to the freedom of speech in the houses. They are not liable to any court proceedings for the speech given in the parliament or its committees. However, it is regulated using the rules guiding such provisions of the house.
  संसद के सदस्यों को सदनों में भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। संसद या उसकी समितियों में दिए गए भाषण के लिए उन पर किसी भी न्यायालय की कार्यवाही नहीं की जा सकती। हालांकि, यह सदन के ऐसे प्रावधानों को निर्देशित करने वाले नियमों का उपयोग करके विनियमित किया जाता है।

Rule of Law

कानून का शासन

- The preamble of the Constitution of India clearly sets out the principles of the rule of law emphasizing justice, equity and freedom.
  भारत के संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कानून के शासन के सिद्धांतों को निर्धारित करती है।
- The rule of law is a legal principle that ensures that everyone is subject to the same laws and held accountable for their actions.
  कानून का शासन एक विधिक सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी समान कानूनों के अधीन हों और अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हों।
- Article 14 of the Constitution assures the equality before the law and equal protection of the law
  संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है

EMERGENCY PROVISIONS

आपातकालीन प्रावधान

The Indian Constitution's emergency provisions allow the President to take extraordinary actions during times of emergency.

भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रपति को आपातकाल के समय असाधारण कार्रवई करने की अनुमति देते हैं।

Article 352 to 360 of the Indian constitution deals with the provisions/rules related to the emergency.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संम्बधित प्रावधानों/नियमों से संबंधित हैं।

As per Article 358, under the emergency provision, article 19 is automatically suspended when the proclamation of emergency is made i.e., it does not require any separate order of suspension.

अनुच्छेद 358 के अनुसार, आपातकालीन प्रावधान के तहत, आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है यानी निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकल नहीं होती।

Under Article 359 the President can suspend the Fundamental Rights during the time of Emergency (Internal and External Emergency).

अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल (आंतरिक और बाहरी आपातकाल) के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं।

Article 20 (Protection against conviction for offences) and Article 21 (Protection of life and personal liberty) cannot be suspended during a national emergency.

अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता।

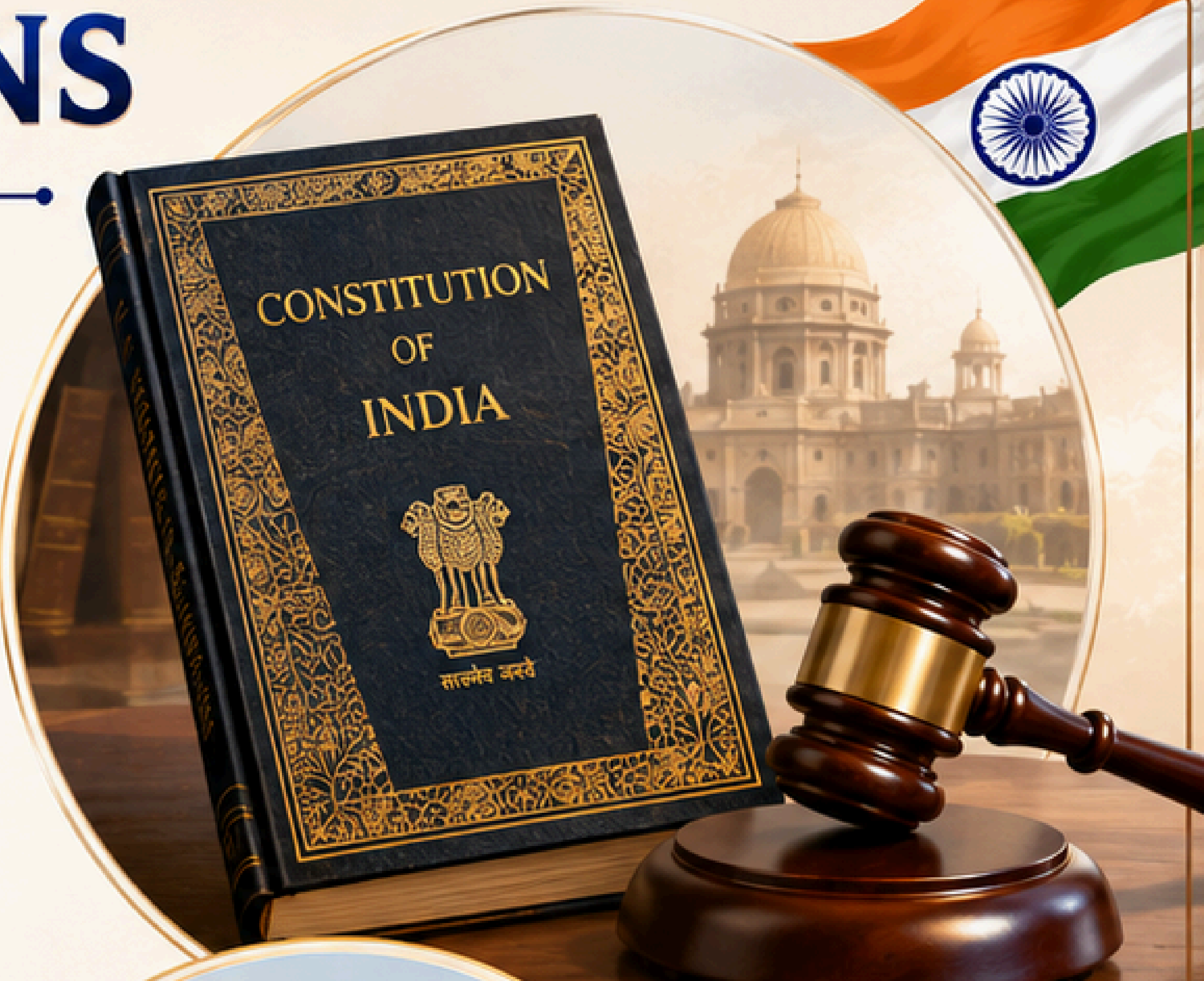

JRF Media Academy by Rohit

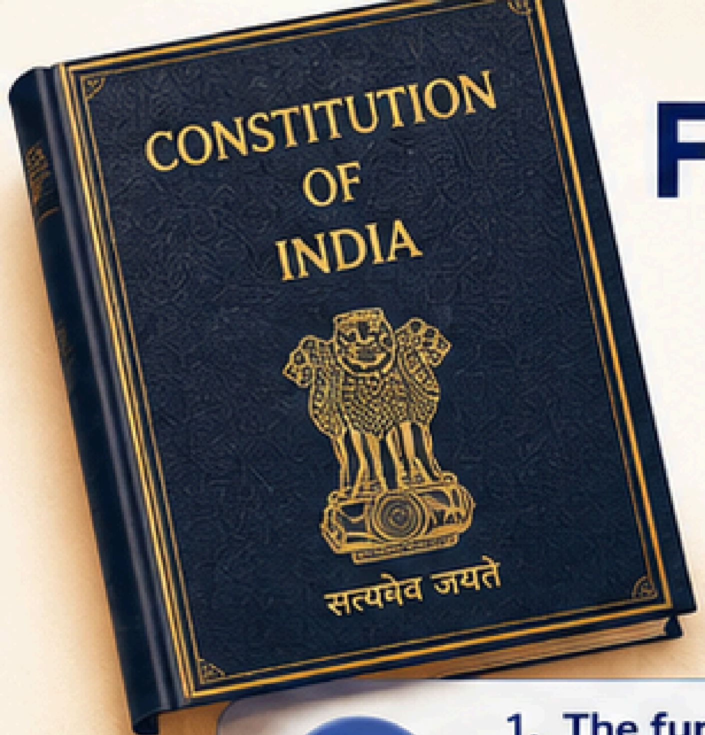

FUNDAMENTAL DUTIES
मौलिक कर्तव्य

1. The fundamental duties are incorporated by the 42nd Amendment to the Constitution in 1976 as Article 51-A in Part IV-A.
   मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भाग IV-A में अनुच्छेद 51-A के रूप में शामिल किया गया।
2. The idea of Fundamental Duties has been borrowed from the Constitution of erstwhile USSR.
   मौलिक कर्तव्यों का विचार पूर्व सोवियत संघ (USSR) के संविधान से लिया गया है।
3. The Indian Constitution outlines 11 fundamental duties for citizens.
   भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।
4. are moral and ethical obligations that promote responsible citizenship and the nation's welfare.
   ये नैतिक और नैतिक दायित्व हैं जो जिम्मेदार नागरिकता और राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देते हैं।

JRF Media Academy by Rohit

FUNDAMENTAL DUTIES
मौलिक कर्तव्य

1) To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem.
संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों तथा संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।

2) To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom.
स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना।

3) To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India.
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना।

4) To defend the country and render national service when called upon to do so.
देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना।

5) To promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women.
धार्मिक, भाषाई तथा क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर भारत के सभी लोगों में सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना; महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना।

6) To value and preserve the rich heritage of our composite culture.
हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का मूल्य समझना और उसकी रक्षा करना।

7) To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures.
प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार करना तथा जीव-जंतुओं के प्रति करुणा रखना।

8) To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform.
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और खोज तथा सुधार की भावना का विकास करना।

9) To safeguard public property and to abjure violence.
सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना।

10) To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.
व्यक्तिगत और सामुहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तरों तक पहुँचे।

11) Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.
जो व्यक्ति माता-पिता या संरक्षक है वह अपने बच्चे या, जैसा भी मामला हो, छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अभिभावक को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

- Articles 36-51 under Part-IV of the Indian Constitution deal with Directive Principles of State Policy (DPSP). They are borrowed from the Constitution of Ireland
  अनुच्छेद 36-51, भाग-IV के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) से संबंधित हैं। ये आयरलेण्ड के संविधान से लिए गए हैं।
- The objective of Directive Principles is to embody the concept of 'welfare state'.
  नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य 'कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा को मूर्त रूप देना है।
- Part IV of the constitution deals with Social, Economic and cultural Rights.
  संविधान का भाग IV सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित है।
- However, they are not justifiable in the court of law.
  हालांकि, ये कानून की अदालत में न्यायोचित नहीं हैं।
- The idea of a 'Welfare State' envisaged in our Constitution can only be achieved if the States endeavor to implement them with a high sense of moral duty.
  हमारे संविधान में परिकल्पित 'कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा तभी हासिल हो सकती है जब राज्य इन्हें उच्च नैतिक दायित्व की भावना से लागू करने का प्रयास करें।
- The DPSPs are not legally enforceable, but they are considered fundamental to the country's governance.
  नीति निर्देशक तत्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत माना जाता हैं।

DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

i. Equal distribution of wealth and material resources among all classes of people so as to prevent its concentration in a few hands. (Art. 38 and 39)

ii. Provision of adequate means of livelihood to all the citizens. (Art. 43)

iii. Equal pay for equal similar work for both men and women. (Art. 39)

iv. Right to work, education and public assistance (Art. 41)

v. Make provision for just and humane conditions of work and maternity relief (Art. 42)

vi. Secure a living wage, a decent standard of living and social and cultural opportunities for all workers (Art. 53)

vii. Take steps to secure the participation of workers in the management of industries (Article 43A)

viii. Article 47 Raise the level of nutrition and the standard of living of people and to improve public health (Article 47)

Universal Adult Franchise

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

One person, one vote is the foundation upon which Indian democracy is based. Elections are open to all Indian citizens who are 18 years old or older, regardless of caste, sex, colour, religion, or status. The mechanism of the universal adult franchise set forth in the Indian Constitution establishes political equality in India.

एक व्यक्ति, एक वोट भारतीय लोकतंत्र की वह मूल आधारशिला हैं जिस पर यह प्रणाली टिकी हैं। चुनाव सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुले हैं जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, चाहे उनकी जाति, लिंग, रंग, धर्म या स्थिति कुछ भी हो। भारतीय संविधान में निहित सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करती हैं।

JRF Media Academy by Rohit

DRAWN FROM VARIOUS SOURCES

विभिन्न स्रोतों से लिया गया

The constitution was drawn from a number of sources.
भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है।

The US Constitution
अमेरिकी संविधान

- Preamble (उद्देशिका)
- Fundamental Rights (Bills of Rights) (मौलिक अधिकार (अधिकार विधेयक)
- Judicial Review (न्यायिक पुनरावलोकन)
- The federal government structure (संघीय सरकार की संरचना)
- Separation of Powers and Independence of the Judiciary (शक्तियों का पृथक्करण और न्याच्यालिका की स्वतंत्रता)
- Review by the courts (न्यायालयों द्वारा पुनरावलोकन)
- The President serving as the Supreme Commander of the Armed Forces. (राष्ट्रपति का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होना)
- Equal legal protection (कानून के समक्ष समान संरक्षण)

British Constitution
ब्रिटिश संविधान

- Parliamentary government (संसदीय शासन प्रणाली)
- Single Citizenship (एकल नागरिकता)
- Rule of Law (कानून का शासन)
- Parliamentary privileges (संसदीय विशेषाधिकार)
- Cabinet system (कैबिनेट प्रणाली)
- Writs (रिट्स)
- Bicameralism (द्विसदनीयता)

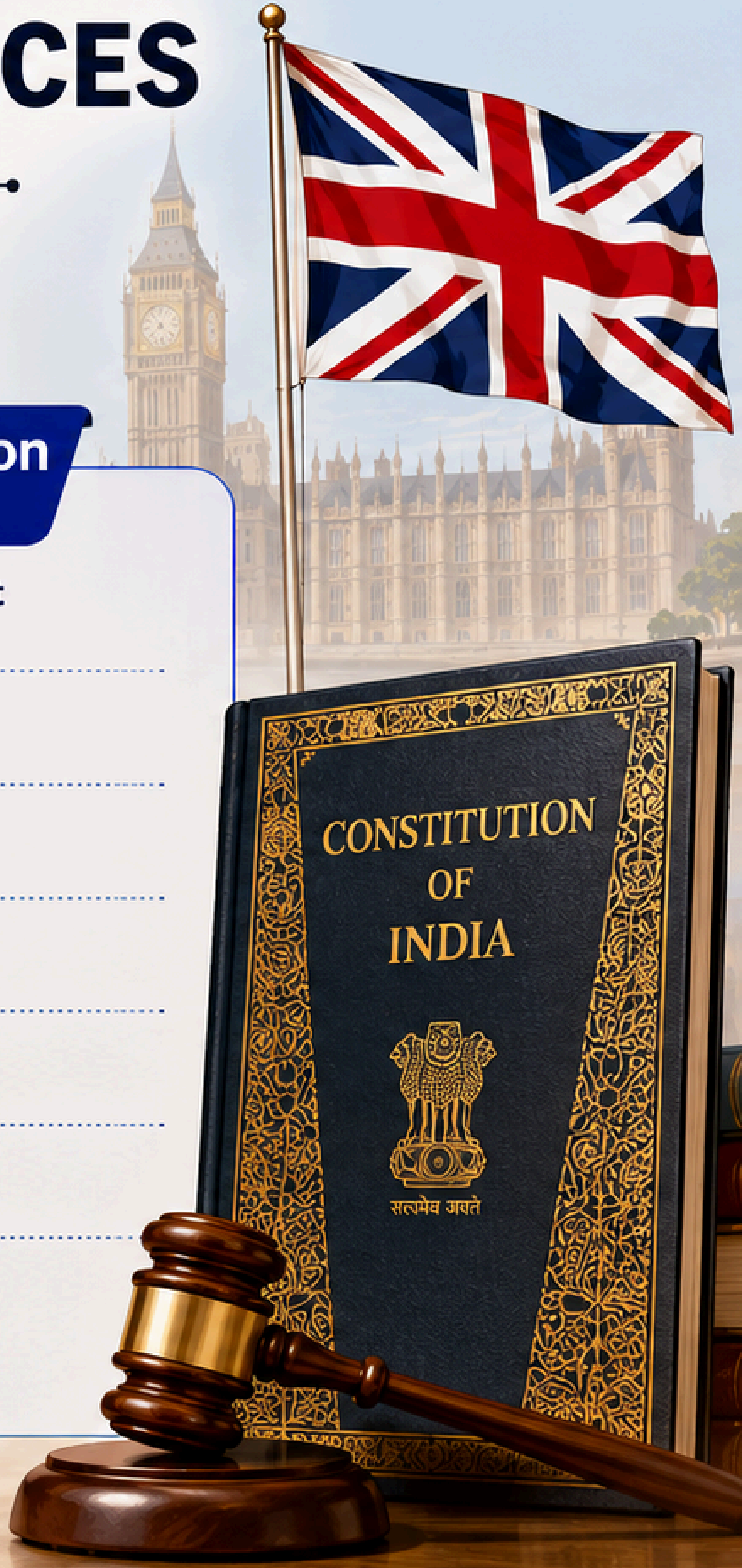

JRF Media Academy by Rohit

Weimer Republic of Germany
वाइमर गणराज्य, जर्मनी

Suspension of fundamental rights during emergency
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन

- Suspension of fundamental rights during emergency
  आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन

VS

Japan
जापान

- Procedure established by law
  कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया
- Laws on which the Supreme Court functions
  वे कानून जिनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है

JRF Media Academy by Rohit

DRAWN FROM VARIOUS SOURCES

The constitution was drawn from a number of sources.

संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है।

AUSTRALIA | ऑस्ट्रेलिया

- Freedom of trade between states
  राज्यों के बीच व्यापार की स्वतंत्रता
- National legislative power to implement treaties, even on matters outside normal federal jurisdiction
  राष्ट्रीय विधायी शक्ति जिससे सामान्य संघीय क्षेत्राधिकार से बाहर के मामलों पर भी संधियों को लागू किया जा सके
- Concurrent List
  समवर्ती सूची
- Provision of Joint Session of the Parliament
  संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान
- Preamble terminology
  उद्देशिका की शब्दावली

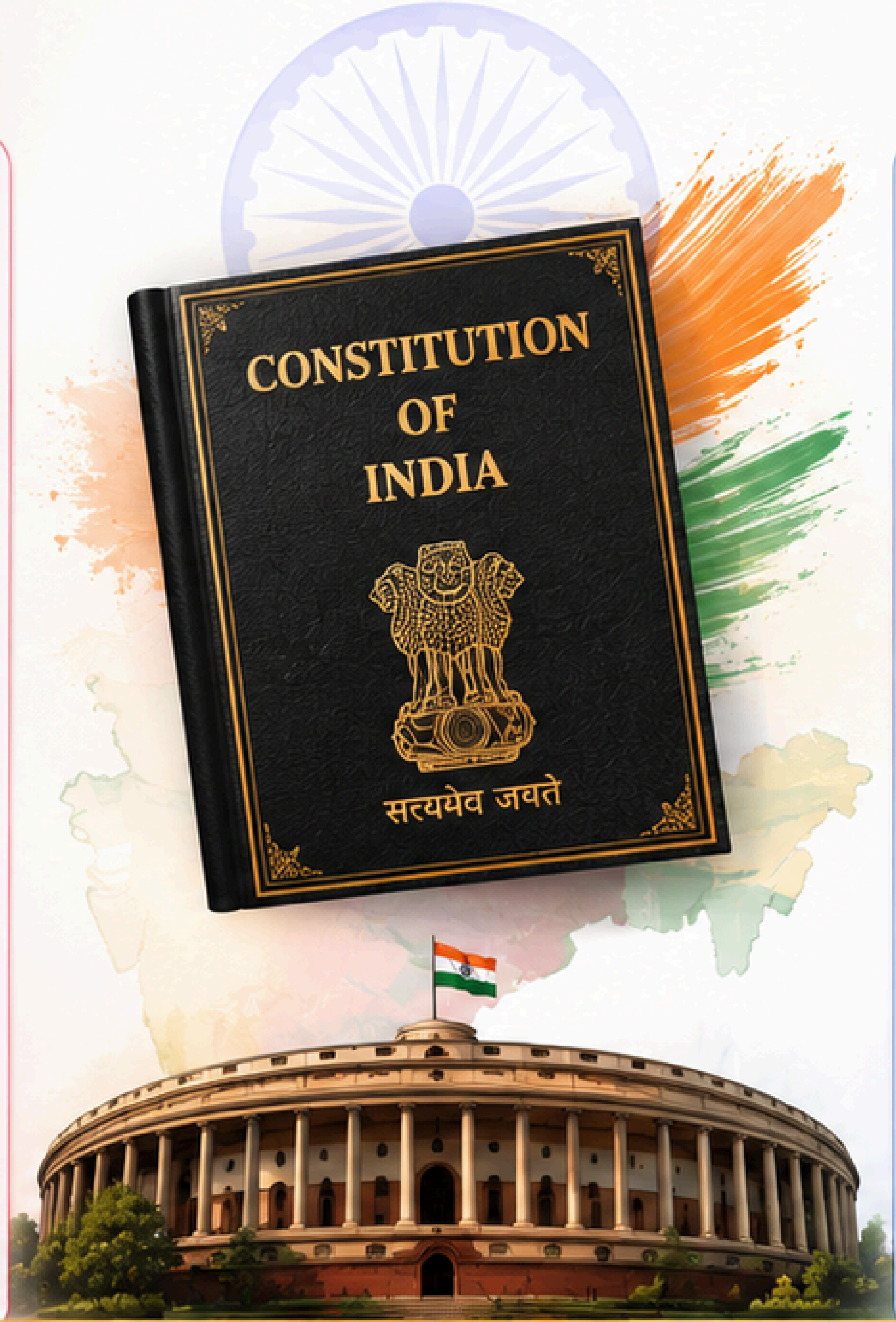

CANADA | कनाडा

- Quasi-federal government—a federal system with a strong central government
  अर्द्ध-संघीय शासन—एक संघीय प्रणाली जिसमें मजबूत केंद्रीय सरकार
- Distribution of powers between the central and state governments
  केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण
- Residual powers, retained by the central government
  अवशिष्ट शक्तियों, जो केंन्द्रीय सरकार के पास सुरक्षित रहती हैं
- Appointment of Governor of states by Centre
  राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा
- Advisory jurisdiction of the Supreme Court
  सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता

JRF Media Academy by Rohit

DRAWN FROM VARIOUS SOURCES
विभिन्न स्रोतों से प्राप्त

Soviet Union
सोवियत संघ

- Fundamental Duties under article 51-A.
  अनुच्छेद 51-A के तहत मौलिक कर्तव्य
- Mandated planning commission to oversee economic development
  आर्थिक विकास की निगरानी के लिए नियोजित योजना आयोग
- Ideals of justice (social, economic and political) in the preamble
  उद्देश्यिका में न्याय के आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)

France
फ्रांस

- Notions of liberté, égalité, fraternité (liberty, equality, fraternity) in the preamble
  उद्देश्यिका में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांत
- The ideals of republic in the preamble
  उद्देश्यिका में गणराज्य के आदर्श

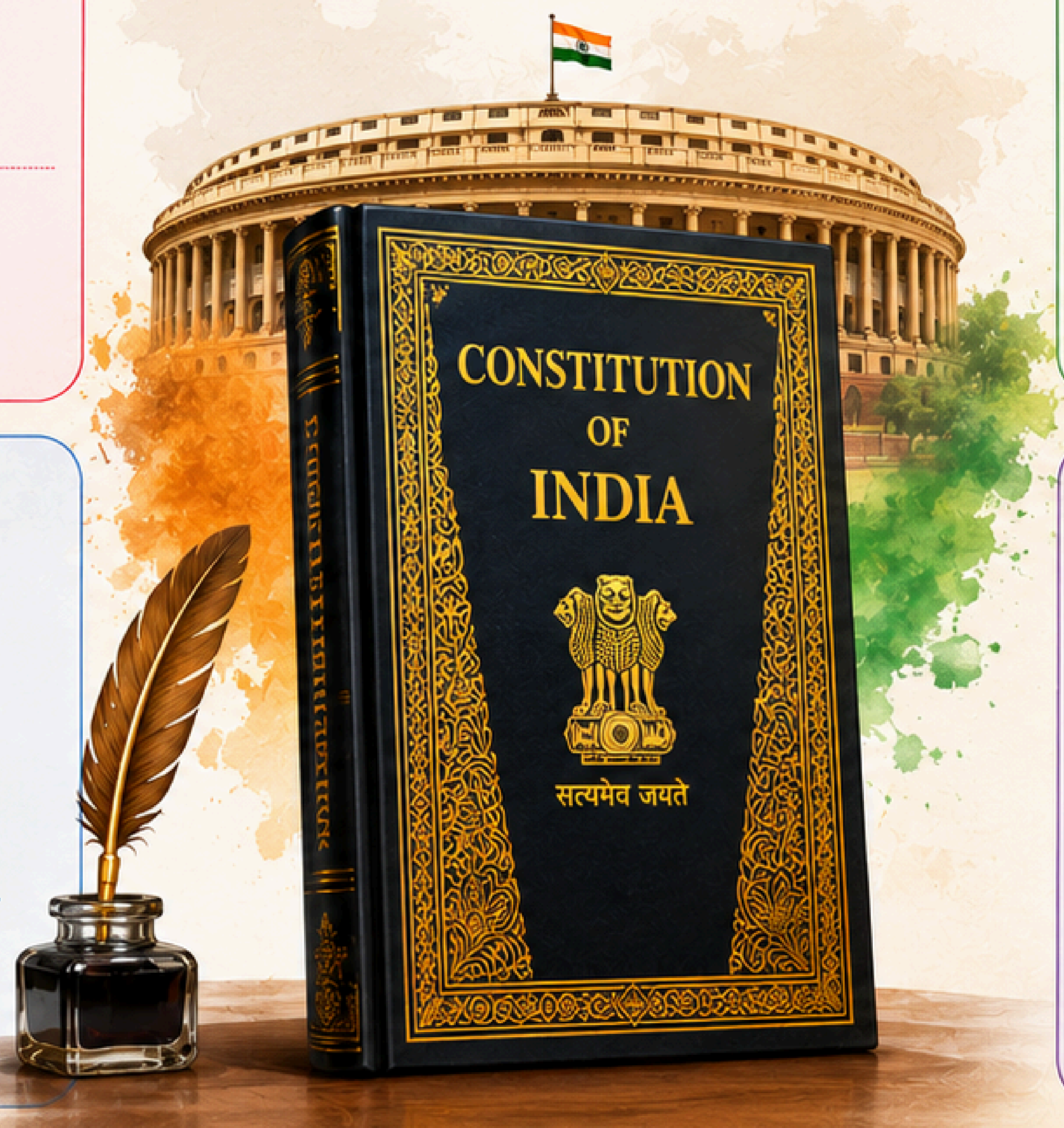

Ireland
आयरलैंड

- Directive principles of state policy
  राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- Nomination of members to the Rajya Sabha by the President
  राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों का नामांकन
- Method of election of the President
  राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि

South Africa
दक्षिण अफ्रीका

- Amendment procedure of the constitution
  संविधान के संशोधन की प्रक्रिया
- Election of members of Rajya Sabha
  राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन

DRAWN FROM VARIOUS SOURCES
विभिन्न स्रोतों से लिया गया है।

The constitution was drawn from a number of sources.
संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है।।

The US Constitution
अमेरिकी संविधान

Fundamental rights, federal structure, judicial review, emphasizing the importance of individual liberties and Separation of Powers and Independence of the Judiciary

मौलिक अधिकार, संघीय संरचना, न्यायिक पुनर्विलोकन, व्यक्मित स्वतंत्रताओं के महत्व, शक्तियों के पृथ्वकरण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जोर

British Constitution
ब्रिटिश संविधान

Parliamentary System, rule of law, legislative procedures, and concept of single citizenship

संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रियाएँ, और एकल नागरिकता की अवधारणा

Irish Constitution
आयरिश संविधान

Directive Principles of State Policy

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व

Soviet Union
सोवियत संघ

Fundamental Duties under article 51-A.
अनुच्छेद 51-A के तहत मौलिक कर्तव्य

Weimar Constitution of Germany
Weimar जर्मनी का संविधान

Suspension of fundamental rights during the emergency
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन

French Constitution
फ्रांसीसी संविधान

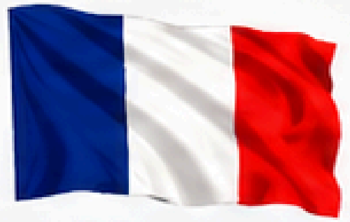

The values of liberty, equality, and fraternity, embodying the democratic ethos and the aspirational goals of the Indian state.
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य, जो लोकतांत्रिक आदर्शों को समाहित करते हैं और भारतीय राज्य के आकांक्षात्मक लक्ष्यों को दर्शाते हैं।

Canadian Constitution
कनाडाई संविधान

Federation with a strong center, Residuary powers of the Centre
मजबूत केंद्र के साथ धंघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तित्यों केंद्र के पास

Japenese Constitution | जापानी संविधान

Procedure established by law

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया

Australian Constitution | ऑस्ट्रेलियाई संविधान

Freedom of trade between states, concurrent List

राज्यों के बीच व्यापार की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची

South Africa | दक्षिण अफ्रीका

Amendment procedure of the constitution

संविधान की संशोधन प्रक्रिया

JRF Media Academy by Rohit